

खबर संक्षेप

ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार

सतना। जीआरपी ने 25 जुलाई को ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच से एक महिला यात्री का पर्स लूटकर भागे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई। जीआरपी आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। हालांकि, अभी तक आरोपी के पास से लूटे गए लाखों के जेवरात बरामद नहीं हो पाए हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम सुमित वर्मा 22 वर्ष है, जो बिरसिंहपुर रामना टोला का निवासी है और प्रेमलाल वर्मा का पुत्र है। ज्ञात हो कि चौक बाजार क्षेत्र निवासी कमल जैन की पत्नी श्वेता जैन 25 जुलाई को ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा कर रही थीं। इसी दौरान आरोपी उनका पर्स लूटकर भाग गया था। महिला यात्री ने घटना की रिपोर्ट जीआरपी सतना में दर्ज करवाई थी। महिला ने शिकायत में बताया था कि पर्स में 7 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात रखे थे। जीआरपी प्रभारी राजेश राज ने अपनी टीम के साथ मामले की जांच पड़ताल की। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों से आरोपी का फुटेज प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर जीआरपी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जिले में अब तक 700.5 मिमी औसत वर्षा दर्ज

सतना। सतना जिले में इस साल 1 जून से 5 अगस्त तक कुल 700.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार, यह पिछले साल इसी अवधि में दर्ज की गई 444 मिमी वर्षा से काफी ज्यादा है। जिले की औसत सामान्य वर्षा 891.7 मिमी है, और अभी तक दर्ज की गई वर्षा इसके करीब है। तहसील-वार आंकड़ों में रघुराजपुर में 839.7 मिमी, सोहावल में 601.7 मिमी, बरौंधा (मझवा) में 880.5 मिमी, बिरसिंहपुर में 624.6 मिमी, रामपुर बाघेलान में 613.9 मिमी, नागोद में 858.4 मिमी, जसो में 355.2 मिमी और उचेहरा में 830.3 मिमी वर्षा हुई है।

मैहर में रोटरी क्लब के गठन की मांग, रेड क्रॉस सोसाइटी की निष्क्रियता पर चिंता

मैहर। जिला बने काफी समय हो चुका है, लेकिन यहां सामाजिक गतिविधियों का संचालन अभी भी धीमा है। इसी को देखते हुए बरिष्ठ समाजसेवी रमापति गौतम ने मैहर में रोटरी क्लब जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था के गठन की मांग की है। उनका कहना है कि रोटरी क्लब जैसी संस्थाएं पीड़ित मानवता की सेवा करती हैं, जो मैहर के लिए अति आवश्यक है। उन्होंने मैहर में पहले से मौजूद रेड क्रॉस सोसाइटी की निष्क्रियता पर भी चिंता जताई है, जो कि केवल औपचारिकता बनकर रह गई है और कोई भी सामाजिक गतिविधि नहीं चला रही है। गौतम ने कहा कि मैहर धार्मिक, साहित्यिक और औद्योगिक क्षेत्र है, जहां सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ऐसी संस्थाओं की मौजूदगी जरूरी है।

त्योहारों को लेकर मैहर पुलिस सतर्क, बाजार में किया पलैंग मार्च

मैहर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर मैहर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। मैहर थाना प्रभारी अनिमेष द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के व्यस्त बाजारों में पलैंग मार्च किया। इस दौरान पुलिस ने दुकानदारों को भीड़ प्रबंधन और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। ठेले और फेरी लगाने वालों को भी सड़क पर यातायात बाधित न करने की सख्त हिदायत दी गई। पुलिस ने आम जनता को भी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की।

अब हर मंगलवार होगा 'सायकिल डे', संभाग आयुक्त के आह्वान पर शुरू हुआ 'सायकिल डे' कलेक्टर सहित कई अधिकारी साइकिल से पहुंचे कार्यालय

सतना। यहां पर मंगलवार को रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद के आह्वान पर कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस समेत कई अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से कलेक्टर पहुंचे। इस अभियान में एसडीएम सिटी राहुल सलाडिया और तहसीलदार रघुराज नगर सोरभ मिश्रा भी शामिल हुए। कलेक्टर ने अपने बंगले से संयुक्त कलेक्टर भवन तक की ढाई किलोमीटर की दूरी 23 मिनट में पूरी की। संभागीय आयुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे हर मंगलवार को 'साइकिल डे' के तहत स्वेच्छा से कार्यालय आने के लिए साइकिल का उपयोग करें।

प्रदूषण पर फोकस

गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कमी आने से वायु प्रदूषण घटेगा इस पहल का मुख्य उद्देश्य ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ कर्मचारियों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना है। इससे निजी और शासकीय पेट्रोल/डीजल वाहनों के उपयोग में कमी आएगी। यह व्यक्तिगत आर्थिक बचत के साथ राष्ट्रीय संसाधनों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में कमी आने से वायु प्रदूषण घटेगा। इससे शहर का पर्यावरण ज्यादा स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक होगा।



साइकिल चलाना व्यायाम भी है

साइकिल चलाना एक बेहतरीन व्यायाम है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। सार्वजनिक परिवहन या ई-स्कूटी से आ सकती है महिला अधिकारी-कर्मचारी क्षेत्र में दौरे के लिए पूल गाड़ी की व्यवस्था की सलाह दी गई है। इसमें दो-तीन अधिकारी समन्वय कर एक ही गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं। इससे योजनाओं का निरीक्षण बेहतर होगा और विभागीय समन्वय से समस्याओं का त्वरित समाधान संभव होगा।

महिला अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विकल्प दिया गया है। वे सार्वजनिक परिवहन या अपनी ई-स्कूटी से कार्यालय आ सकती हैं।

ये पहल पूरी तरह स्वैच्छिक

यह पहल पूरी तरह स्वैच्छिक है। आयुक्त रीवा संभाग ने सभी से अपील की है कि वे इसमें सक्रिय भागीदारी निभाकर इसे सफल बनाएं। यह न केवल एक संस्थागत उत्तरदायित्व है बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी भी है।



मैहर कलेक्टर ने 3 किमी पैदल चलकर की 'साइकिल दिवस' पहल की शुरुआत

पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए मैहर संभाग में एक नई पहल शुरू की गई है। अब से हर मंगलवार को 'साइकिल दिवस' मनाया जाएगा, जिसमें सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी साइकिल या पैदल चलकर दफ्तर आएंगे। इस पहल की शुरुआत मैहर

कलेक्टर श्रीमती रानी बाटड़ ने की, जो 3 किलोमीटर पैदल चलकर अपने दफ्तर पहुंचीं। उनके साथ अपर कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार सहित कई अधिकारी और कर्मचारी भी साइकिल और पैदल आए। यह पहल बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की कीमतों को देखते हुए शुरू की गई है। अधिकारियों को मंगलवार को पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों का उपयोग न करने का निर्देश दिया गया है। महिला अधिकारी ई-स्कूटी या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर सकती हैं।

जनसुनवाई: समस्याओं के समाधान के लिए उमड़ रही भीड़



सतना। सरकारी कार्यालयों में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सतना जिले में जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। यह जनसुनवाई लोगों के लिए अपनी बातों को सीधे अधिकारियों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गई है। हाल ही में कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में, कलेक्टर डॉ.सतीश कुमार एस ने जिले के विभिन्न हिस्सों से आए 121 आवेदकों की समस्याओं को सुना। कलेक्टर ने अपर कलेक्टर सुधीर बेक और डिप्टी कलेक्टर बीके मिश्रा के साथ मिलकर सभी आवेदकों से उनके आवेदन प्राप्त किए और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। कुछ मामलों का मौके पर ही समाधान करने के निर्देश दिए गए, जबकि बाकी सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को कार्यवाही के लिए भेज दिया गया।

नगर निगम में जनसुनवाई

इसी तरह, नगर निगम में भी महापौर योगेश ताम्रकार और नगर निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी ने जन सुनवाई की। इस दौरान कुल 47 आवेदक उपस्थित हुए। जनसुनवाई में सबसे अधिक 13 शिकायतें पीएम आवास से संबंधित थीं। इसके अलावा, अतिक्रमण शाखा से 5, योजना शाखा से 2, पेयजल शाखा से 4, निर्माण शाखा से 2, ईपीएफ शाखा से 1, विद्युत शाखा से 1, संपत्ति कर शाखा से 2 और स्वास्थ्य शाखा से 2 शिकायतें प्राप्त हुईं। महापौर और नगर निगम अध्यक्ष ने भी कुछ शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया और शेष आवेदनों को संबंधित शाखाओं के प्रभारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया। जनसंपर्क अधिकारी धीरज मिश्रा ने बताया कि

जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं को लेकर लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराने आ रहे हैं। यह जनसुनवाई इस बात का प्रमाण है कि जनता को सरकारी विभागों से जुड़ी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार उमड़ रही भीड़ इस बात को दर्शाती है कि लोगों को अपने कामों के लिए अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अधिकारियों द्वारा मौके पर समाधान किए जाने से कुछ लोगों को तुरंत राहत मिल रही है, लेकिन शेष आवेदनों पर होने वाली कार्यवाही का इंतजार अभी भी जारी है।

मैहर जिले की जनसुनवाई में आए 28 आवेदन

मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में, मैहर की कलेक्टर रानी बाटड़ ने जिले के अलग-अलग हिस्सों से आए 28 आवेदकों की शिकायतों को सुना। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह और एसडीएम विकास सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। कलेक्टर ने हर आवेदन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया और यह सुनिश्चित किया कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो। इस जनसुनवाई का उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवाओं तक सीधी पहुंच प्रदान करना और उनकी समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना है।

मैहर में मोबाइल कोर्ट ने 12 वाहनों से वसूला 32 हजार का जुर्माना

मैहर। यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। बायपास स्थित केजेएस सीमेंट फैक्ट्री तिराहा और इंडियन कैफे हाउस के सामने मैहर-कटनी और मैहर-रीवा रोड पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उदयाजीत कुंवर राव ने मोबाइल कोर्ट लगाकर कार्रवाई की। इस दौरान बस, ट्रक, ऑटो और अन्य भारी वाहनों की जांच की गई। कुल 12 वाहनों को रोक कर उनके बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट की जांच की गई। दस्तावेज अधूरे पाए जाने पर वाहन चालकों पर कुल 32,500 का जुर्माना लगाया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और रेलवे स्टेशन के पास वाहनों की लंबी लाइन लग गई। इस कार्रवाई का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना था।



दिनदहाड़े जेवरों से भरा बैग लेकर भागे बदमाश, पुलिस जांच में जुटी

मैहर। दिनदहाड़े चोरी की एक बड़ी घटना सामने आई है। रक्षाबंधन से पहले एक आभूषण व्यापारी से लाखों के जेवर से भरा बैग चोरी हो गया। यह घटना रामनगर तहसील में हुई, जहां संतोष सोनी नाम के व्यापारी सुबह करीब 11 बजे अपनी दुकान पर पहुंचे। दुकान का ताला खोलते समय पहले से घात लगाए बैठे दो बदमाशों ने उनकी मोटरसाइकिल से जेवरों से भरा बैग चोरी कर लिया और फरार हो गए। संतोष सोनी ने तुरंत रामनगर थाना पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी विजय त्रिपाठी ने बताया कि चोरी हुए जेवरों की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए है। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी तलाश कर रही है।



मैहर-बरही मार्ग की खस्ताहाल सड़क से लोग परेशान, मरम्मत के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

मैहर। मैहर से बरही को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की खराब हालत से लोग परेशान हैं। जगह-जगह गड्ढे होने से आप दिन हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं या अपाहिज हो गए हैं। इस मार्ग से हर रोज हजारों लोग, छात्र और व्यापारी गुजरते हैं। सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने सड़क के गड्ढों को भरने और साइड शोल्डर बनवाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही सड़क की मरम्मत नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार टोल टेकेदार और एमपीआरडीसी सहित संबंधित विभाग पर कार्रवाई की मांग की है।



बेला पुलिस चौकी के पास 8 मवेशियों की मौत

सतना। रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र में रीवा-मैहर मार्ग पर स्थित नेशनल हाईवे-30 पर बेला पुलिस चौकी के ठीक सामने एक अज्ञात वाहन ने 9 मवेशियों को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 5 गायों और 3 बैलों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बैल गंभीर रूप से घायल है। रूट पेट्रोलिंग अधिकारियों के मुताबिक, इस मार्ग पर रोजाना 15 से 20 आवारा मवेशी हादसों का शिकार हो रहे हैं। इस घटना ने गौशालाओं के खाली होने और सड़क पर आवारा मवेशियों की बढ़ती संख्या पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सड़कों पर कोई मवेशी नहीं दिखेगा।

ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सतना। ट्रक एसोसिएशन ने ओवरलोडिंग और अवैध खनिज परिवहन को रोकने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन ने जनसुनवाई में बताया कि हाईकोर्ट और भारत सरकार के आदेश के बावजूद आज तक किसी भी ओवरलोड वाहन पर धारा 199 के तहत कार्रवाई नहीं की गई है। उनका कहना है कि जिले की 10 में से 8 गाड़ियां ओवरलोड होती हैं, जिससे सड़कें खराब हो रही हैं और दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। एसोसिएशन ने कलेक्टर से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

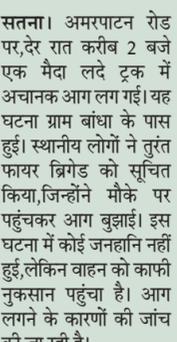
बकाया राशि जमा न करने पर दुकान सील

सतना। शहर के बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार रघुराजपुर सोरभ मिश्रा ने स्टेशन रोड स्थित फर्म 'लेखनी देखनी' को सील कर दिया। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि फर्म के मालिक अशोक कोटवानी ने आरआरसी जारी होने के बाद भी बकाया 4 लाख रुपए की राशि जमा नहीं की थी। राजस्व विभाग ने कुर्की को कार्रवाई के तहत फर्म को मशीनों और अन्य सामान भी जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही अन्य बड़े बकायेदारों पर भी कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।



चलते ट्रक में लगी आग बड़ा हादसा टला

सतना। अमरपाटन रोड पर, देर रात करीब 2 बजे एक मैदा लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। यह घटना ग्राम बांधा के पास हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित किया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन को काफी नुकसान पहुंचा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।





खतरपुर नगर पालिका ने लॉन्च किया

स्वच्छता अलार्म ऐप

खतरपुर। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए खतरपुर नगर पालिका ने एक अजूबी पहल शुरू की है। नदरअखल नगर पालिका ने स्वच्छता के लिए अलार्म बजने वाला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और ऐसी पहल करने वाली देश में पहली बार नगर पालिका बन गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों को कचरा प्रबंधन में सहूलियत प्रदान करना है। नगर पालिका परिषद की मुख्य नगर पालिका अधिकारी माधुरी शर्मा ने बताया कि स्वच्छ नगर खतरपुर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप को खसियत यह है कि जैसे ही स्वच्छता वाहन आपके घर के पास पहुंचेगा वैसे ही आपके मोबाइल पर अलार्म बजेगा और आप समय पर कचरे को कचरा वाहन में डाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर स्वच्छ नगर खतरपुर सर्व करके डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा, नगर पालिका द्वारा जारी व्हाट्सएप कोड को स्कैन करके भी इसे इंस्टॉल किया जा सकता है। सीएमओ ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

रिक्शा चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी से मिला सुराग



खतरपुर। बरेठी निवासी रामदीन यादव, जो इन दिनों छत्रखानगर में रह रहे हैं, 23 जुलाई 2025 को जिला अस्पताल खाना देने गए थे। जब वे वापस लौटे तो उनका रिक्शा मौके से गायब था। इसके शिकारत रामदीन ने सिटी कोतवाली में दर्ज कराई। थाना प्रभारी अरविंद दानी ने बताया कि पुलिस ने तत्काल सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की और आरोपी की पहचान अजय अहिरवार, निवासी बगौला के रूप में की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिक्शा भी बरामद कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

ब्रह्माकुमारीज द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित किया कार्यक्रम



खतरपुर। प्रजापति ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा बक्सवाहा के ग्राम बीरमपुरा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ग्राम वासियों के लिए एक प्रेरणादाई कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर खतरपुर विध्वनय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा ने कहा कि नशा केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी कर्मजोर करता है। इससे व्यक्ति का जीवन, परिवार और समाज दोनों प्रभावित होते हैं। उन्होंने सभी को नशा मुक्त जीवन की प्रतिष्ठा कराई और सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने का आह्वान किया। बीके पूजन ने राजयोग ध्यान के माध्यम से मन को शांत व सशक्त बनाने के तरीके बताए। ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और नशा छोड़ने की प्रतिष्ठा ली। इस अभियान के माध्यम से संस्था का उद्देश्य है कि भारत को नशा मुक्त बनाकर एक स्वस्थ, सुखी और नैतिक समाज की स्थापना की जा सके।

छतरपुर जेल में बंदियों से मुलाकात के लिए प्रशासन ने की खास व्यवस्था

रक्षाबंधन पर छतरपुर जेल में बंधेगा स्नेह का बंधन

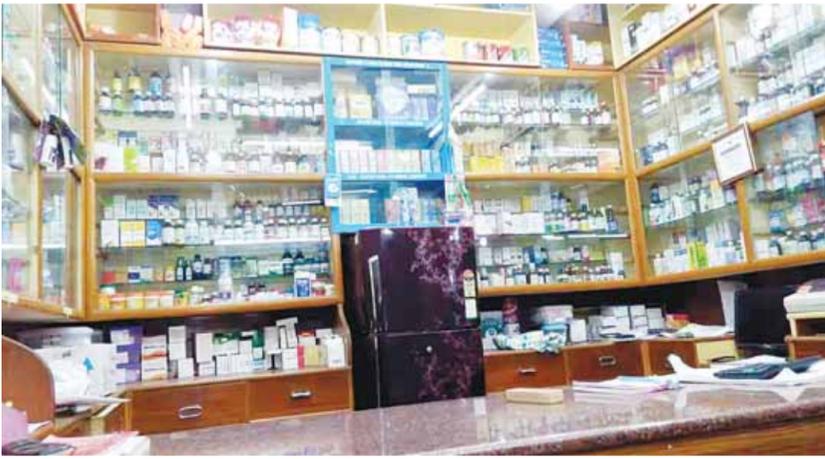
छतरपुर।

आगामी रक्षाबंधन के पर्व पर जिला जेल में बंदियों को उनके परिजनों से मिलने का अवसर प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इस मौके पर महिला परिजनों और बच्चों को पुरुष बंदियों से मिलने की अनुमति होगी, जबकि महिला बंदियों के भाइयों को भी निर्धारित समय में मुलाकात का मौका मिलेगा। जेल प्रशासन ने सुचारु संचालन के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन अनिवार्य होगा। छतरपुर जिला जेल अधीक्षक दिलीप सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन पर बंदियों के परिजनों को उनसे मुलाकात की सुविधा दी जाएगी, भले ही

जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिक संचालित होने के साथ साथ किराए के लाइसेंस पर मेडीकल स्टोर भी संचालित हो रहे हैं। अधिकांश मेडीकल स्टोर किराए के लाइसेंस पर चलते हैं और उनके पास कोई फार्मासिस्ट भी नहीं है। लेकिन घडल्ले से दवाईया बेची जा रही है।

हरिभूमि न्यूज, छतरपुर।

ड्रग इंस्पेक्टर इन कतिपय मेडीकल संचालकों पर मेहरबान है उनका फीलगुड हर माह ऐसे मेडीकल संचालकों से होता है। जिससे किसी की जांच नहीं होती है यहां तक देखा जा रहा है। कुछ नाबालिग बच्चे भी बच्चे मेडीकल स्टोरों पर पूरे दिन दवाई बेचने का काम करते हैं जबकि यह नाबालिग बच्चे मुस्किल से आठवीं या दसवीं पास होते हैं। फिर भी डॉक्टर द्वारा लिखे पर्चों पर घडल्ले से मरीजों को दवाईया दे रहे हैं। बैसे भी शहर में गली गली में मेडीकल स्टोर खुले हुए हैं। कुछ प्रतिष्ठित मेडीकल स्टोर को छोड़कर सभी मेडीकल स्टोर किराए के लाइसेंस पर संचालित हो रहे हैं जिन लोगों ने फार्मासिस्ट की डिग्री प्राप्त कर रखी है और मेडीकल खोलने का लाइसेंस प्राप्त कर रखा है। उन लोगों द्वारा अपना मेडीकल लाइसेंस 50 हजार से लेकर 1 लाख रूपय सालाना में किराए पर दे दिया गया है। यदि प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग एवं ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से शहर में संचालित नए नए मेडीकल स्टोरों की जांच कराई जाए, तो किराए के लाइसेंस पर चल रहे मेडीकल स्टोरों का खुलासा हो जाएगा। लेकिन जांच कौन



करे यदि जांच की जाएगी तो हर माह का फीलगुड बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ड्रग इंस्पेक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में जानकारी नहीं है। उन्हें सब पता है कि कौन मेडीकल स्टोर किराए के लाइसेंस पर चल रहा और कौन मेडीकल स्टोर फार्मासिस्ट चला रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि इनकी भी मजबूरी यह है कि यदि कार्यवाही की जाती है तो हर माह का फीलगुड बंद हो जाएगा कई मेडीकल स्टोर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड को पूरा भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास पर्याप्त जगह मेडीकल स्टोर खोलने के लिए नहीं है फिर भी ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा निरीक्षण करने के बाद

उन्हें लाइसेंस देने के लिए हरी झण्डी दे दी जाती है। ऐसा खेल लम्बे समय से चल रहा है नाबालिगों के माध्यम से मेडीकल स्टोर में दवाई विक्रवाना खतरों से खाली नहीं है फिर भी जिम्मेदार अधिकारी मूकदर्शक बने हुए हैं।

नशीली दवाओं से होती लाखों की कमाई

शासन द्वारा खासकर स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध के बाद इन दवाओं को मेडीकल स्टोरों पर नहीं बिकना चाहिए लेकिन युवा पीढ़ी को नशे की ओर

धकेलने और अबैध कमाई के चक्कर में कई मेडीकल स्टोरों में नशीली दवाएं बिक रही हैं। जिसका उपयोग युवा पीढ़ी के लोग नशे के लिए कर रहे हैं पुलिस अधीक्षक द्वारा नशे से दूरी अभियान चलाया जा रहा है लेकिन कतिपय मेडीकल संचालक पुलिस अधीक्षक के इस अभियान को धता बता रहे हैं और युवाओं को खुलेआम दुगनी कीमत पर नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बेच रहे हैं। जिन मेडीकल स्टोरों में नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बिक रही है उन मेडीकल स्टोरों में शाम के समय युवा पीढ़ी के लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। नशीली और प्रतिबंधित दवाएं बेचने वाले मेडीकल स्टोरों में कोड बताने पर नशीली चीजें उपलब्ध करा दी जाती है। कोड शब्द का उपयोग करने पर मेडीकल स्टोर में उपस्थित अन्य लोग कुछ समझ भी नहीं पाते और युवाओं को नशीली दवा मिल भी जाती है। बस इतना है कि दुगुना रेट बसूला जाता है। ऐसे में मेडीकल स्टोर संचालकों की लाखों की कमाई हो रही है और युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पर पहुंच रही है।

कुछ एमआर ने बताया कि यूपी से बिकने आ रही दवाएं

सूत्रों(एमआर) से पता चला है कि कुछ प्राइवेट लोग भी मेडीकल से संबंधित दवाएं बेचने का काम कर रहे हैं और यह लोग यूपी से सस्ते दामों पर दवाएं लाते हैं और छतरपुर में चोरी छिपे इसका कारोबार करते हैं। यह भी चर्चा है कि महोबा जिले के बेलाताल में खुलेआम सस्ते दरों पर दवाएं बेचने का कारोबार किया जा रहा है। और छतरपुर के कुछ लोग जो मेडीकल व्यवसाय से चोरी छिपे जुड़े हुए हैं। वह दवाएं लाकर शहर में सप्लाय कर रहे हैं। हनुमान तौरिया के पीछे एक मेडीकल स्टोर में इस तरह की दवाएं बेची जा रही है इसी तरह देरी रोड और सटई रोड में भी मेडीकल स्टोर की आड़ में कुछ लोग दवाओं का अबैध कारोबार संचालित कर रहे हैं।

सड़कों पर बैठ रहा अवारा गौवंश, युवाओं ने जनसुनवाई में की शिकायत अतिक्रमण की चपेट में हैं गौशालाएं और गौचर भूमि

छतरपुर।

जिला मुख्याल सहित पूरे जिले की सड़कों पर इन दिनों आवारा गौवंश बैठ रहा है, जिसके चलते आए दिन हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। गौवंश के लिए जिले में बनाई गई गौशालाओं और आवंटित की गई गौचर भूमियों पर अवैध कब्जे कर लिए गए हैं, जिससे आक्रोशित युवाओं ने मंगलवार को जनसुनवाई में आवेदन दिया।

आवेदन देने पहुंचे युवा सुधीर पांडे ने बताया कि सरकार ने गौवंश की सुरक्षा के लिए गौशालाएं बनाई हैं और गौचर भूमि आवंटित की है लेकिन इनका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं दिख रहा। गौशालाओं और गौचर भूमि पर अवैध कब्जा



कर लिया गया है, जिसके कारण बेसहारा गौवंश सड़कों पर घूम रहा है। सड़कों पर बैठे गौवंश के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिनमें न

केवल गौवंश बल्कि लोग भी घायल हो रहे हैं और कुछ की जान भी जा रही है। युवाओं ने जिला प्रशासन से मांग की कि गौशालाओं

को कब्जा मुक्त कर गौवंश को वहां स्थानांतरित किया जाए और गौचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

प्राथमिक शाला के संविलियन का ग्रामीणों ने किया विरोध जनसुनवाई में आवेदन देकर बच्चों की शिक्षा पर जाहिर की चिंता

छतरपुर।

जिला मुख्यालय के समीपी ग्राम पलौठा के ग्रामीणों ने शासकीय प्राथमिक शाला के संविलियन के खिलाफ आवाज उठाई है। मंगलवार को जिला मुख्यालय की जनसुनवाई में उन्होंने आवेदन देकर मांग की कि गांव के स्कूल का संविलियन संदीपनी विद्यालय में न किया जाए, क्योंकि इससे बच्चों को स्कूल जाने में भारी परेशानी होगी और उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। ग्राम पलौठा के सिराज खान सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव की शासकीय प्राथमिक शाला का संविलियन, संदीपनी विद्यालय (सीएम राईज) में करने की योजना है। संविलियन होने से स्कूल की दूरी गांव से लगभग सात किलोमीटर हो जाएगी और छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचने में कठिनाई होगी। गांव में ज्यादातर किसान और मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, जो अपने काम-धंधे छोड़कर बच्चों को इतनी दूर स्कूल नहीं ले जा पाएंगे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि प्राथमिक शाला का संविलियन रोका जाए और इसे गांव में ही यथावत रखा जाए, ताकि छोटे बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो।

सामने आए राजस्व और अतिक्रमण के मामले, त्वरित निराकरण के निर्देश कलेक्टर ने नौगांव में सुनी जनता की समस्याएं

नौगांव।



नगर में तहसील स्तर पर पहली बार आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इस अजूबी पहल के तहत राजस्व, पुलिस और अतिक्रमण से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया, जबकि जनसुनवाई के बाद वृक्षारोपण पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक कलेक्टर पार्थ त्रिसेवाल द्वारा हर मंगलवार को जिले की अलग-अलग तहसीलों में की जा रही जनसुनवाई की पहल के तहत नौगांव के कृषि विज्ञान केंद्र हॉल में तहसील स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। उनके साथ जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह परिहार, जिला शिक्षा अधिकारी आरपी प्रजापति, नौगांव एसडीएम

बृजभान पटेल, तहसीलदार पीयूष दीक्षित, नौगांव सीएमओ आरएस अस्वार्थी, नौगांव एसडीओपी अमित मेश्राम सहित अन्य विभागों के अधिकारी और तहसील स्तर के कर्मचारी मौजूद रहे। जनसुनवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई और लगभग 2 बजे तक चली, जिसमें आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे। कुल 185 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सबसे अधिक राजस्व से संबंधित मामले थे, इसके अलावा

कुछ पुलिस और अतिक्रमण से जुड़े मामले भी सामने आए। ग्राम लहादरा के दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने गौचर जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत दोहराई, आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली जनसुनवाई में तहसीलदार को आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कलेक्टर ने तहसीलदार को तत्काल जांच और कार्रवाई का आदेश दिया। जनसुनवाई के बाद कलेक्टर और

अधिकारियों ने कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।

पूर्व विधायक ने सौंपा जनसमस्याओं का ज्ञापन

तहसील स्तरीय जनसुनवाई के दौरान महाराजपुर के पूर्व कांग्रेसी विधायक नीरज दीक्षित ने भी कलेक्टर को जनसमस्याओं पर आधारित सात बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा। उक्त ज्ञापन में पूर्व विधायक श्री दीक्षित ने पिछले दिनों हुई अत्यधिक बारिश से किसानों को हुए व्यापक नुकसान का सर्वे कराने, स्मार्ट मीटर के कारण हो रही समस्याओं का समाधान कराए जाने, जनपद में भारी भ्रष्टाचार किए जाने जैसे मुद्दे उठाकर कलेक्टर को विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर ने उनका ज्ञापन स्वीकार कर निराकरण करने का आश्वासन दिया।

छतरपुर।

शहर में पिछले दिनों हुई चोरी की तीन घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो चोरों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई की है। चोरों के कब्जे से एक लाख रुपये नकद, चांदी के आभूषण और सिलेंडर सहित डेढ़ लाख रुपये से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है।

सिविल लाइन थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे ने बताया कि थाना क्षेत्र के नरसिंहगढ़ पुरवा, चौबे कॉलोनी और लोकनाथपुरम में हुई चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामले दर्ज किए थे। विवेचना के दौरान पुलिस ने पिछले दिनों चतुर्भुज अभियान के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का फुटेज निकाला और इसीकी मदद से पुलिस चोरों तक पहुंची। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने नरसिंहगढ़ पुरवा और लोकनाथ पुरम



में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी मुन्नु उर्फ अरुण पुत्र नारायण दास नामदेव निवासी जमुनिया पुलिसिया सागर रोड खतरपुर को गिरफ्तार किया। उसके पास से चांदी के आभूषण, मॉडर से चोरी किया गया एलपीजी सिलेंडर सहित नकद पैसे बरामद हुए। इसी तरह चौबे कॉलोनी में चोरी करने वाले आरोपी अंशुल पुत्र बृजकिशोर

भारद्वाज निवासी ग्राम महेंबा को भी पकड़ा गया जिसके पास से करीब 1 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति बरामद की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि एक आरोपी मुन्नु नामदेव खतरपुर और टीकमगढ़ जिले के विभिन्न थानों में दर्ज चोरी के नौ अपराधों में पहले से संलिप्त है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।

नाले में बाइक सहित बहे वन चौकीदार का दो दिन बाद मिला शव किशनगढ़ पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने की तलाश

बिजावर।



किशनगढ़ वन परिक्षेत्र में दो दिन पहले वन विभाग का का चौकीदार तेज बहाव वाले नाले में अपनी बाइक सहित बह गया था। दो दिन की कठिन तलाश के बाद मंगलवार को आखिरकार उसका शव बरामद हुआ, जिसे पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। शव की तलाश में किशनगढ़ पुलिस, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम ने दिन-रात मेहनत की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रविवार की देर शाम को किशनगढ़ वन परिक्षेत्र के गहरी घाट में तैनात चौकीदार रघुवीर पुत्र जहान सिंह, उम्र 30 वर्ष, निवासी ककरा नरौली अपनी बाइक से ड्यूटी के लिए जा रहा था। उसके साथ दशरथ नामक

व्यक्ति भी था, जो पटोरी गांव के पास बुड्डेना नाले में तेज बहाव देखकर बाइक से उतर गया। जब रघुवीर ने नाले को पार करने की कोशिश की, तभी तेज धारा में वह बाइक सहित खाई में बह गया। सूचना मिलते ही किशनगढ़ थाना प्रभारी और पुलिस दल मौके पर पहुंचे।

सोमवार सुबह वन विभाग की टीम, एसडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर तलाश शुरू की, लेकिन उस दिन न तो रघुवीर का पता चला और न ही उसकी बाइक बरामद हुई। लगातार बचाव कार्य में जुटी किशनगढ़ पुलिस, वन विभाग और एसडीआरएफ की टीम ने मंगलवार

सुबह लगभग 7 बजे रघुवीर का शव नाले में तैरता हुआ पाया। किशनगढ़ थाना प्रभारी और पुलिस बल की मौजूदगी में शव का पंचनामा तैयार किया गया और उसे पोस्टमार्टम के लिए बिजावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।



खबर संक्षेप

कलेक्टर ने निर्माणाधीन सेंट्रल लाइब्रेरी भवन का किया निरीक्षण



रीवा । कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सेंट्रल लाइब्रेरी के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया तथा अब तक की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देश दिये कि सितंबर माह तक कार्य पूर्ण कराये ताकि अक्टूबर से सेंट्रल लाइब्रेरी का विधिवत नवीन भवन में संचालन प्रारंभ हो सके। उल्लेखनीय है कि 2 करोड़ 46 लाख रुपये की लागत से बनाये जा रहे सेंट्रल लाइब्रेरी भवन में 160 पाठकों के बैठकों की व्यवस्था रहेगी तथा बुक सेल्फ सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी। कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया कि लाइब्रेरी भवन के सामने लान बनाये तथा उद्यमों बेंच या कुर्सी की व्यवस्था कराये साथ ही किनारे के रिक्त स्थल में वरिष्ठ पाठकों के लिये लान बनाकर कुर्सी व बेंच की व्यवस्था करे। निरीक्षण के दौरान सहायक यंत्री हाउसिंग बोर्ड हिमांशु वर्मा एवं निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कमिश्नर रीवा की अनूठी पहल पर्यावरण और स्वास्थ्य रक्षा के लिए एक दिन साइकिल कमिश्नर तथा अधिकारी-कर्मचारी साइकिल से पहुंचे कार्यालय

रीवा । रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के लिए लगातार कई नवाचार कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, ईंधन की बचत और आमजन को स्वास्थ्य रक्षा का संदेश देने के लिए संभाग के सभी जिलों में मंगलवार को सुमंगल साइकिल अभियान शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन कमिश्नर तथा सभी वरिष्ठ अधिकारी और अधिकतर कर्मचारी साइकिल से कार्यालय पहुंचे। जो व्यक्ति आयु अथवा स्वास्थ्य के कारण साइकिल चलाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं उन्हें ई स्कूटी, ई रिक्शा और पैदल कुछ दूर चलकर वैकल्पिक वाहन से कार्यालय आ सकते हैं। अभियान के पहले दिन अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी साइकिल से ही कार्यालय पहुंचे। सभी संभागीय अधिकारी कमिश्नर आवास में एकत्रित होकर



कमिश्नर श्री जामोद के नेतृत्व में साइकिल चलाते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और साप्ताहिक समीक्षा बैठक में शामिल हुए। साइकिल चलाने में महिला अधिकारियों ने भी सहभागिता निभाई। संभाग के साथ-साथ सभी जिलों में भी कलेक्टर तथा जिला स्तरीय अधिकारी साइकिल से कार्यालय पहुंचे। इस संबंध में कमिश्नर जामोद ने कहा कि मंगलवार के दिन को साइकिल डे के रूप में चुना गया है। संभाग के सभी अधिकारियों और

कर्मचारियों से स्वैच्छिक रूप से साइकिल से कार्यालय आने का निर्देश दिए गये है। विभिन्न संगठनों तथा आमजनता से भी सप्ताह में एक दिन बड़े सवारी वाहनों को छोड़कर साइकिल का उपयोग करने का आह्वान किया गया है। इसके माध्यम से एक ओर जहाँ पर्यावरण और ऊर्जा का संरक्षण होगा वहीं दूसरी ओर साइकिल चलाने से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। हम सबने बचपन और युवावस्था में साइकिल का खूब उपयोग किया है। अब छोटी सी दूरी के लिए भी हम वाहन का उपयोग करने लगे हैं। इस आदत को छोड़कर हम सब जहाँ तक संभव हो वहाँ साइकिल का उपयोग करें। साइकिल चलाना डॉक्टरों के अनुसार सबसे अच्छा व्यायाम है। साइकिल से कार्यालय आने के अनुभव को साझा करते हुए जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक प्रवीण पाठक ने

कहा कि अधिकारियों के साथ साइकिल चलाकर सामूहिकता की अनुभूति होती है। हमें अंदर से महसूस होता है कि हम ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में उच्च योगदान दे रहे हैं। सुमंगल साइकिल दिवस अभियान प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में सहायक होगा। डिप्टी कमिश्नर श्रेयस गोखले ने कहा कि मंगलवार का दिन जनसुनवाई का दिन है। जब हम साइकिल से कार्यालय आते हैं तो हमारा माइंडसेट बदल जाता है। अब आमजनता से अधिक जुड़ाव महसूस हो रहा है। यह भी सुशासन का एक रूप है। सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, संभागीय प्रबंधक मार्कफेड नेहा पीयूष तिवारी, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे तथा अन्य अधिकारियों ने भी साइकिल से कार्यालय आने के अनुभव साझा किए।

बारिश के बाद अजगर पहुंचा रिहायशी इलाके में, खेत में बिल्ली को निगला



देखने लगे तो उन्हें एक बड़ा अजगर बेसुध अवस्था में पड़ा मिला। पास जाकर देखने पर पता चला कि अजगर ने एक बिल्ली को निगल लिया था। निगलने के कुछ देर बाद ही बिल्ली की मौत हो गई, लेकिन अजगर उसे पचा नहीं पाया और कुछ ही समय बाद उसने बिल्ली को उल्टी कर पेट से बाहर निकाल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर का रेस्क्यू किया और उसे एक बोरी में डालकर पास के जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। ग्रामीणों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अजगर ने बिल्ली को पूरी तरह निगल लिया है और बाद में उसे बाहर निकाल देता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जंगलों में रहने वाले जीवों के प्राकृतिक आवास जलमग्न हो गए हैं। भोजन और गर्मी की तलाश में ये जानवर अब मानव बस्तियों की ओर भटकने लगे हैं।

रीवा। लगातार हो रही बारिश के चलते जंगलों में रहने वाले जीव-जंतु अब भोजन और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं। रीवा जिले के त्योंहर क्षेत्र अंतर्गत टिकुरी गांव में ऐसा ही एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक विशालकाय अजगर ने खेत में घूम रही एक बिल्ली को निगल लिया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, टिकुरी गांव निवासी किसान अरुण सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उन्हें पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। अजगर ने पास जाकर देखने पर पता चला कि अजगर ने एक बिल्ली को निगल लिया था। निगलने के कुछ देर बाद ही बिल्ली की मौत हो गई, लेकिन अजगर उसे पचा नहीं पाया और कुछ ही समय बाद उसने बिल्ली को उल्टी कर पेट से बाहर निकाल दिया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। कुछ ग्रामीणों ने हिम्मत दिखाते हुए अजगर का रेस्क्यू किया और उसे एक बोरी में डालकर पास के जंगल में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया। ग्रामीणों ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि अजगर ने बिल्ली को पूरी तरह निगल लिया है और बाद में उसे बाहर निकाल देता है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जंगलों में रहने वाले जीवों के प्राकृतिक आवास जलमग्न हो गए हैं। भोजन और गर्मी की तलाश में ये जानवर अब मानव बस्तियों की ओर भटकने लगे हैं।

जनसुनवाई में 64 आवेदकों की सुनी गई समस्याएं

रीवा । कलेक्टर ने आयोजित जनसुनवाई में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी एवं संयुक्त कलेक्टर राजेश सिन्हा ने 64 आवेदकों की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित आवेदनों को विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया।जनसुनवाई में मध्यपुर के निवासियों ने शासकीय भूमि एवं शासकीय हैण्डपंप को अतिक्रमण मुक्त करने का आवेदन दिया जिसे बनकड़या स्कूल के नायब तहसीलदार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। रमपुरवा निवासी अमेशिया, बुडवा निवासी रामाधर, गोविंदगढ़ निवासी मुद्रिका प्रसाद बर्हेलिया के सीमांकन के आवेदनों में संबंधित तहसीलदारों को कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया। इसी प्रकार मदनलाल रजक निवासी बहेरा के नक्शा तस्वीर को कम्प्यूटर में दर्ज करने एवं राजेन्द्र सिंह जोड़ावपुर निवासी के खसरा सुधार के आवेदनों में संबंधित एसडीएम को कार्यवाही करने के लिये प्रेषित किया गया। लोही निवासी लालमणि तिवारी के सड़क का मुआवजा दिलाये जाने के आवेदन को एसडीएम हुजूर को, गया प्रसाद साकेत घोषी निवासी के फर्जी ऋण पुस्तिका की जांच कराने के आवेदन को एसडीएम मगवां को तथा आशीषाचार्य अमवा निवासी के जर्जर भवन को गिराने के आवेदन एसडीएम हुजूर को कार्यवाही के लिये प्रेषित किया गया। इसी प्रकार कुसुम पाण्डेय निवासी पुष्पराज नगर ने अवैध कब्जा हटाने का आवेदन दिया जिसे तहसीलदार हुजूर को, चन्द्रशेखर विश्वकर्मा मंडीयारी निवासी के सत्यापित नकल प्रदाय करने के आवेदन को नकल शाखा को तथा रायपुर सोनौरी निवासी संकटमोचन गौतम के अवैध बाड़ी को हटाने के आवेदन को नायब तहसीलदार रायपुर सोनौरी को कार्यवाही करने के लिये प्रेषित किया गया। कुतुलिया निवासी मोतीमणि के संबल से सहायता राशि दिलाये जाने तथा बरा निवासी राजेश सिंह के आम रास्ता से अतिक्रमण हटाने के आवेदनों पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया।

प्रशासन के आदेश की अनदेखी

सरकार के ई पंचायत का सपना अधूरा, पंचायतों के नहीं खुलते ताले



मऊगंज। आज आधुनिक युग में सभी कार्य डिजिटल हो जिसके लिए शासन स्तर पर ग्रामीण सेवा को बेहतर बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों के काम हो जिसके लिए ई पंचायत की व्यवस्था की गई है। पंचायत स्तर पर ई पंचायत संबंधी सभी सिस्टम प्रदान किए गए हैं। लेकिन जमीनी हालात देखे जाएं तो सरकार का ई पंचायतगांव जैसा सपना सरकार नहीं हो पा रहा है जिसका सबसे बड़ा कारण यह देखा जा रहा है कि अधिकतर ग्राम पंचायतों में पंचायत संबंधी कार्य होना तो दूर पंचायत भवनों के नियमित ताले तक नहीं खुलते। सरकार के मसानुसार क्षेत्र में निवास करने वाली ग्रामीण जनता को जनपद कार्यालयों तक पहुंचाने का चक्कर न कान्ना पड़े इसके लिए शासन ने सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराया है। पंचायत को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने के लिए प्रति पंचायत भवन पर कई लाख रुपये की तकनीकी सामग्रियों के नाम पर खर्च किए गए हैं। सभी पंचायतों में ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक की नियुक्ति की गई है लेकिन इसका लाभ आम लोगों को सुचारु रूप से नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि अधिकतर पंचायत भवनों में ताले लटकते देखे जाते हैं। हकीकत देखी जाए तो या ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिवों के झोले में सील एवं रजिस्टर होते हैं या फिर ग्राम पंचायत में रहने वाली अधिकतर आवश्यक सामग्री इन जिम्मेदारों के घरों की शोभा बढ़ा रही है। पंचायती राज व्यवस्था के तहत सरकार की मंशा है कि पंचायत भवन को निम्नी सचिवालय के रूप में विकसित करना है जहां ग्रामीणों की फरियाद सुनकर उनकी समस्याएं दूर की जा सकें। लेकिन सरकार द्वारा की गई इतनी बड़ी व्यवस्था के बाद भी पंचायत भवनों की स्थिति यथावत है। गांव का भ्रमण करने पर चौकाने वाली सच्चाई सामने नजर आती है जहां से विकास विभाग की योजनाएं चलती हैं वहां के पंचायत भवनों में न केवल ताला लटकना नजर आता है बल्कि कई पंचायत भवनों के पल्लर प्रत्यक्ष रूप से जाहिर होता नजर आता है कि इन ग्राम पंचायतों के ताले कभी कमान विशेष अवसर पर ही खुलते हैं। कई ग्राम पंचायतों के परिसर में खर-पतवार एवं बाल

उगी हुई देखी जा सकती है। *जनपद पंचायत में आदेशों का नहीं होता पालन*सरकार द्वारा जारी निर्देश के बाद भी ग्राम पंचायतों में पदस्थ जिम्मेदारों की मनमानी से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिले में कई ऐसी ग्राम पंचायत हैं जिनके पंचायत भवनों का ताला ही नहीं खुलता। क्षेत्र की अधिकतर ग्राम पंचायतों के हाल इसी तरह है जहां विशेष अवसरों को यदि छोड़ दिया जाए तो गांव की सरकार ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव के घर से संचालित होती है। ग्रामीणों के चर्च के दौरान बताया कि पंचायत भवन आए दिन बंद रहते हैं जिसके कारण छोटे-छोटे कार्यों के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। पंचायती राज व्यवस्था में जहां जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत को नियमित शासकीय अंकांश को छोड़कर कार्यालय खोलने का प्रावधान है प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत स्तर के अनेक कार्य संचालित होते हैं। पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत का लेखा-जोखा तैयार करना और ग्राम स्तर पर ही निपटारा करना होता है इसके अलावा परिवार रजिस्टर की नकल जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाना, जांच कार्ड के अलावा अन्य कई कार्य करना होता है। लेकिन शासन के मंसानुसार नियमित ग्राम पंचायतों के न खुलने के कारण ग्रामीण जनता को ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव के घर या फिर जनपद कार्यालय भटकना पड़ता है। ग्राम पंचायत भवनों से ई सेवा सामग्री ग्राह्य शासन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जमीनी रूप देने एवं पंचायत स्तर के सभी कार्य पंचायत कार्यालय में करने तथा आधुनिक तकनीक की व्यवस्था के साथ सभी कार्यों के संपादन हेतु बड़ी रकम खर्च कर हर पंचायत में एलईडी एवं कंप्यूटर सिस्टम आदि सामग्री की व्यवस्था की गई है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि यदि कुछ निम्नी चुनी ग्राम पंचायत को यदि छोड़ दिया जाए तो आज की स्थिति में 80 फ्रीसदी ग्राम पंचायतों के एलईडी एवं कंप्यूटर सिस्टम ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिवों के घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। प्रशासनिक उद्देश्यों के चलते कई जगह तो ऐसे भी हालत हैं कि पूर्ण सरपंचों द्वारा वर्तमान पंचायतों में चुने गए सरपंचों को एलईडी एवं कंप्यूटर सिस्टम दिया ही नहीं गया। ग्राम पंचायत कार्यालय में ई ग्राम पंचायत जैसी आधुनिक व्यवस्था की सामग्री ना रखी जाने के कारण और अधिकतर ग्राम पंचायत का नियमित ताला न खोलने एवं शासन तथा प्रशासन के निर्देशानुसार पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक का पंचायत में न बैठने के कारण ग्राम वासियों को यहां वहां भ्रमण करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि जनपद एवं जिले में बैठे अधिकारियों को इस विषय की जानकारी नहीं है बल्कि हकीकत यह है कि यह जिम्मेदार अधिकारी जानकर भी अंजान बने हुए हैं।

सोहागी घाटी में दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित ट्रक पलटा, एक की मौत, दो गंभीर घायल



रीवा। जिले के सोहागी घाटी एक बार फिर सड़क हादसे का गवाह बनी है। सोमवार रीवा-प्रयागराज मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैलर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा गया। इस हादसे में ट्रक में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक सहित दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैलर ट्रक रीवा से प्रयागराज की ओर जा रहा था। जैसे ही वाहन सोहागी घाटी के दलान पर पहुंचा, चालक संतुलन खो बैठा और ट्रक बैकवुड होकर पलट गया। हादसे में ट्रैलर का अलावा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक में सवार अमरेश यादव, निवासी बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, चालक चेतनम यादव और खलासी मोहम्मद जखार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से ट्रक से बाहर निकालकर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही सोहागी थाना प्रभारी पवन शुक्ला अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ट्रैलर में तीन लोग सवार थे। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया है और घायलों का इलाज जारी है। मौतदाह है कि सोहागी घाटी क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस द्वारा नशे में वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, बावजूद इसके हादसों की संख्या में कोई खास कमी नहीं आई है।

रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों के निराकरण पर सभी अधिकारी विशेष ध्यान दें। इसमें 50 दिन से अधिक समय से लंबित सभी आवेदन पत्रों का सात दिवस में निराकरण करें। संभागीय अधिकारी प्रत्येक दिन जिला अधिकारियों द्वारा आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करें। निचले स्तर तक जाकर आवेदनों में कार्यवाही करके ही इनका निराकरण संभव होगा। खाद्य विभाग, गृह विभाग ने पिछले सप्ताह अच्छा निराकरण किया है। पीएचई, कृषि, ट्राईबल, ऊर्जा, राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। कमिश्नर ने कहा कि अब सभी अधिकारी ई ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों और पत्र भेजें। महत्वपूर्ण सूचनाओं और रिपोर्ट को भी ई ऑफिस के माध्यम से ही प्रस्तुत करें। अधीनस्थ जिलाधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिलाकर कार्यालयीन कामकाज ई ऑफिस के माध्यम से करें। लंबित पेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। सभी अधिकारी 31 जुलाई तक सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पेशन प्रकरण 15 दिवस में पेशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें। संभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन सात दिवस में अतिव्यय रूप से ऑनलाइन दर्ज करा दें। कमिश्नर ने कहा कि एक पेड़ में के नाम अभियान में सभी प्रगति सतोषजनक नहीं है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पौधे रोपित करके उनकी सुरक्षा के उचित प्रबंध करें। नेबलन हड्डे तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम हाइवे के डिवाइडरों में पौधे रोपित कराएं। सभी शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों और आंगनवाड़ी केन्द्र परिसरों में भी भूमि उपलब्ध होने पर पौधे उतखण रोपित कराएं। अब तक वन विभाग द्वारा 4619048, जल संसाधन विभाग द्वारा 4704, लोक निर्माण विभाग द्वारा 4781, ऊर्जा विभाग द्वारा 3710, पीआइएचू द्वारा 4369, सड़क विकास निगम द्वारा 8540 तथा शिक्षा विभाग द्वारा 85970 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 26526 पौधे रोपित किए गए हैं।

सीएम हेल्प लाइन में 50 दिन से अधिक के आवेदनों का निराकरण करें

रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि सीएम हेल्प लाइन प्रकरणों के निराकरण पर सभी अधिकारी विशेष ध्यान दें। इसमें 50 दिन से अधिक समय से लंबित सभी आवेदन पत्रों का सात दिवस में निराकरण करें। संभागीय अधिकारी प्रत्येक दिन जिला अधिकारियों द्वारा आवेदनों के निराकरण की समीक्षा करें। निचले स्तर तक जाकर आवेदनों में कार्यवाही करके ही इनका निराकरण संभव होगा। खाद्य विभाग, गृह विभाग ने पिछले सप्ताह अच्छा निराकरण किया है। पीएचई, कृषि, ट्राईबल, ऊर्जा, राजस्व, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। कमिश्नर ने कहा कि अब सभी अधिकारी ई ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों और पत्र भेजें। महत्वपूर्ण सूचनाओं और रिपोर्ट को भी ई ऑफिस के माध्यम से ही प्रस्तुत करें। अधीनस्थ जिलाधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिलाकर कार्यालयीन कामकाज ई ऑफिस के माध्यम से करें। लंबित पेशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। सभी अधिकारी 31 जुलाई तक सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के पेशन प्रकरण 15 दिवस में पेशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें। संभागीय समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन प्रतिवेदन सात दिवस में अतिव्यय रूप से ऑनलाइन दर्ज करा दें। कमिश्नर ने कहा कि एक पेड़ में के नाम अभियान में सभी प्रगति सतोषजनक नहीं है। निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पौधे रोपित करके उनकी सुरक्षा के उचित प्रबंध करें। नेबलन हड्डे तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम हाइवे के डिवाइडरों में पौधे रोपित कराएं। सभी शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों और आंगनवाड़ी केन्द्र परिसरों में भी भूमि उपलब्ध होने पर पौधे उतखण रोपित कराएं। अब तक वन विभाग द्वारा 4619048, जल संसाधन विभाग द्वारा 4704, लोक निर्माण विभाग द्वारा 4781, ऊर्जा विभाग द्वारा 3710, पीआइएचू द्वारा 4369, सड़क विकास निगम द्वारा 8540 तथा शिक्षा विभाग द्वारा 85970 एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 26526 पौधे रोपित किए गए हैं।

मार्च महीने में हुई हिंसा, गांव की रफ्तार थाम कर रख दी

गड़रा गांव में घटना के 4 महीने बाद भी भय और बेबसी का साया... ?

प्रशासन की ओर से गांव में भरोसे और सहयोग के पुनर्स्थापना की पहल, ताकि घाव भरे और गांव आगे बढ़े

मऊगंज। जिले में 15 मार्च 2025 को दिल को दहला देने वाली घटी घटना का वेदना भरा दिन शाहपुर थाना क्षेत्र के गड़रा गांव को आज भी तथाकथित डर और दुख के अंधकार में डकेले हुए है। घटना के ठीक 4 महीने बाद भी गांव के हालात उस तरह से सामान्य नहीं हो पाए जैसा चाहिए। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा गांव की स्थिति को सामान्य दौर में लाने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं और किया जा रहे हैं प्रशासन की ओर से गांव में भरोसे और सहयोग के पुनर्स्थापना की पहल भरे प्रयास किए जा रहे हैं।

बता दें की गत 15 मार्च को शनि द्विवेदी की निर्मम हत्या और बचाव में पहुंची पुलिस टीम पर हुए हमले में उपनिरीक्षक रामचरण गौतम की शहादत ने न केवल जिले को झकझोर कर रख दिया बल्कि हिंसा में दर्जन भर अधिकारी कर्मचारी घायल हुए थे उसके बाद गांव में धारा 144 लागू हुई। घरों पर ताले लटकने लगे, खेत बंजर हो गए और कई परिवार छिन्न-भिन्न हो गए, इस छोटे से गांव के विकास एवं दिनचर्या की रफ्तार भी थाम कर रख दी।

थमी सी है जिंदगी, गांव में सन्नाटे जैसे हालात

जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गड़रा गांव की गलियों में आज 4 महीने बाद भी पुलिस का पहरा है, लोग डरे-सहमे अपने घरों तक सिमटे हैं। कई मकानों पर या तो ताले लटके हैं, या फिर परिवार जेल में हैं, या हिंसा के बाद से गांव छोड़ चुके हैं और आज तक उनकी घर वापसी नहीं हुई। गड़रा कांड में अब तक 39 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी 10 फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि स्थिति सामान्य हो रही है लेकिन जमीनी सच्चाई इससे अलग है।

ग्रामीणों की परेशानी उन्हीं को जुबानी टूट गया हाथ, छिन गई रोटी-

गड़रा गांव निवासी निर्मला साकेत उन महिलाओं में हैं जिसे बिना किसी दोष के बर्बरता का सामना करना पड़ा। पीड़ित का आरोप है कि 17 मार्च को पुलिस ने उसके घर में घुसकर पति और बेटे को उठाया और मारपीट में उसका हाथ भी तोड़ दिया। केवाईसी अधूरी होने के कारण राशन मिलना बंद हो गया। खेत उजड़ गया, मवेशी भूख मरने लगे, और जिन घरों में वह



मजदूरी करती थीं, वहां से भी काम छिन गया। पवन का दर्द, एक साथ तीन अर्थियां- मार्च महीने की 15 तारीख को गड़रा गांव में हुई हिंसा के बाद 4 अप्रैल को गांव में एक और हृदय विदारक दृश्य सामने आया, जब पवन साकेत के पिता औशेरी 55 वर्ष, बहन मीनाक्षी 11 वर्ष और भाई अमन 8 वर्ष के शव घर में फांसी के फंदे पर झूलते पाए गए। पवन ने बताया कि प्रशासन ने मुआवजे का वायदा किया था, पर अब तक एक रुपया नहीं मिला। हम बांस काटकर, लकड़ी बेचकर जीवन निर्वाह रहे हैं। दिव्यांग बेटे को भी नहीं बख्शा- गड़रा गांव में घटित घटना की लपेट में आए स्थानीय निवासी शिवरतन ने बताया कि उसके दिव्यांग बेटे बृजभान, जो चलने-फिरने में असमर्थ है, को भी पुलिस ने आरोपी मानकर जेल भेज दिया। पीड़ित शिवरतन ने आरोप लगाते हुए कहा कि पेट के ऑपरेशन से उबर रहे बृजभान को जबरन उठा लिया गया। अब वह रीवा के अस्पताल में जीवन और न्याय दोनों के लिए संघर्ष कर रहा है। बच्चों की पढ़ाई ठप, पुलिस चौकी बना स्कूल जिले के अंतर्गत गड़रा गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में

विद्यार्थियों को उपस्थित और पढ़ाई के बजाय पुलिस की तैनाती देखने को मिली। हालांकि उपस्थित पुलिसकर्मियों ने कहा कुछ बच्चे स्कूल आते हैं। इधर आंगनवाड़ी में भी सन्नाटा पसरा रहा। शिक्षा और बचपन पर इस त्रासदी का गहरा असर पड़ा है। जिसके चलते आज घटना के 4 महीने बाद भी गांव में ना तो पुरानी रौनक लौटी है और ना ही लोगों के चेहरे पर खुशी। हालात कुछ इस कदर जैसे गांव की खुशी एवं चैन पर काली छाया पड़ गई हो। शासन की योजनाएं जहां प्रभावित हैं वहीं देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों की पढ़ाई, माता-पिता के भविष्य की सारी लालसाएं जैसे खत्म हो गई हो। चिंतन है तो सिर्फ दर्द भरे उदात्त दिन का जिसके कारण आज यह दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन ने कहा पता नहीं वह दिन कब आएगा जब प्रहण की छाया से हम सब उबर पाएंगे, कब लौटेंगे गांव में खुशियां, कब बच्चों की चहल-पहल भरी वह रौनक आएगी ? कब लौटेंगे वह गांव का भाई चारा ? गांव के लोगों ने दर्द भरे लहजे में कहा जाति वर्ग विभेद को दरकिनार कर काकु कक्का काकी जैसी आवाजें सुनने के लिए जहां कान तरस गए, वहीं आंखें धोमिल हो गईं। गांव के वर्तमान जो हालात हैं उससे जाहिर होता है गड़रा गांव की कहानी सिर्फ एक हिंसा की नहीं, बल्कि उसके बाद की चुपियों, कराहों और अन्याय की भी है। हर घर से एक स्वर उठ रहा है दोषियों को सजा जरूर मिले, लेकिन निर्दोषों को न्याय मिलना चाहिए। स्थिति अब सामान्य, सामाजिक समरसता की ओर अग्रसर

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह परिहार ने कहा कि गड़रा गांव में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई पुलिस ने गहन जांच के लिए विशेष टीम में गठित की थी। अब तक 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जबकि 10 अन्य अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल था, जो सामाजिक स्तर पर भी व्याप्त था। ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने ग्रामीणों के सहयोग से स्थिति को संभालने का सतत प्रयास किया। आज जनजीवन काफी हद तक सामान्य हो चुका है। अधिकांश प्रवासी मजदूर भी गांव लौटे आए हैं और पुनः खेती-किसानी तथा अन्य कार्यों में जुट गए हैं। सामाजिक वैमनस्य को दूर करने हेतु प्रशासन ने विभिन्न समुदायों के साथ संवाद की प्रक्रिया अपनाई है। सामूहिक बैठकों के माध्यम से सोहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है ताकि गांव की साझा संस्कृति और सह-अस्तित्व बना रहे, उन्हीं में मऊगंज और अन्य गांवों के निवासियों से अपील करते हुए कहा हम सभी को मिलकर शांति, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सोहार्द्र बनाए रखना है। यदि किसी के मन में कोई शंका या पीड़ा है, तो वह बेहिचक प्रशासन से संवाद करे। हम सबके लिए सदैव उपलब्ध हैं। मुझे विश्वास है कि गांव अब स्थिरता की ओर बढ़ रहा है और भविष्य में यह सामूहिक समरसता का प्रतीक बनेगा।

मऊगंज कलेक्टर ने सुमंगल साइकिल दिवस में साइकिल से पहुंचे कार्यालय



उठाया गया है। कलेक्टर के साथ इस अभियान में उनके निज सहायक पंकज श्रीवास्तव, रोडर सहित अन्य कार्यालय स्टाफ के भी सहभागिता निभाई। कलेक्टर कार्यालय परिसर में पहुंचने के बाद उन्होंने सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों से इस पहल को हर मंगलवार नियमित रूप से अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 'विश्व भर में बढ़ते पर्यावरण अदसुलन और ईंधन की लगातार हो रही कमी को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम सभी अपने स्तर से प्रयास करें। हर मंगलवार को साइकिल से कार्यालय आने से न केवल स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी और पर्यावरण संतुलन में भी योगदान मिलेगा।' कलेक्टर ने यह भी बताया कि संभागायुक्त महोदय की इस अभिनव सोच के तहत पूरे रीवा संगम के सभी विभाग प्रमुखों को यह निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक मंगलवार को साइकिल से कार्यालय आए। यदि मौसम प्रतिकूल हो, जैसे बरसात के दिन हों, तो ई-रिक्शा या ई-स्कूटी का भी उपयोग किया जा सकता है। इस अभियान का उद्देश्य आम जनता में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना है और यह संदेश देना है कि छोटे-छोटे बदलावों से भी बड़ा प्रभाव संभव है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों और आम नागरिकों से इस अभियान को नैतिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाने की अपील की है। यह पहल मऊगंज में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रथम प्रयागदायक कदम के रूप में देखी जा रही है।

